बिहार विशेष · Bihar Special

बिहार आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन, पटना जलापूर्ति व औद्योगिक भूमि को कैबिनेट मंजूरी

बिहार की पहली ई-कैबिनेट बैठक में राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद (BEAC) गठन, पटना जलापूर्ति हेतु ₹1,794 करोड़ तथा 38 ज़िलों में मुफ़्त कोचिंग केंद्रों सहित 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बिहार विशेष · Bihar Special

1. बिहार की पहली पेपरलेस ई-कैबिनेट

- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पहली डिजिटल ई-कैबिनेट बैठक संपन्न।
- प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े कुल 34 प्रस्तावों को मंजूरी।

बिहार विशेष · Bihar Special

2. बिहार आर्थिक सलाहकार परिषद (BEAC)

- PMEAC की तर्ज पर 5 सदस्यीय आर्थिक परिषद का गठन।
- प्रख्यात अर्थशास्त्री होंगे अध्यक्ष, वित्त सचिव (व्यय) होंगे पदेन सचिव।

बिहार विशेष · Bihar Special

3. पटना जलापूर्ति और औद्योगिक विस्तार

- अमृत 2.0 के तहत ₹1,794 करोड़ की पटना जलापूर्ति परियोजना स्वीकृत।
- नालंदा, समस्तीपुर व शेखपुरा में 1294 एकड़ औद्योगिक भूमि का अधिग्रहण।

बिहार विशेष · Bihar Special

4. युवा और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा

- सभी 38 ज़िलों में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुफ़्त कोचिंग केंद्र।
- ग्राम कचहरी का वार्षिक प्रशासनिक अनुदान ₹4,000 से बढ़कर ₹24,000।

परीक्षा के लिए तथ्य · Facts for Exams

याद रखें

Remember

निकाय का नाम	बिहार आर्थिक सलाहकार परिषद (BEAC)
BEAC की अधिकतम सदस्य संख्या	5 (अध्यक्ष सहित)
BEAC के पदेन सचिव	सचिव (व्यय), वित्त विभाग
पटना जलापूर्ति परियोजना परिव्यय	₹1,794.32 करोड़ (अमृत 2.0)
औद्योगिक भूमि अधिग्रहण क्षेत्र	1,294.37 एकड़ (3 ज़िले)
औद्योगिक भूमि अधिग्रहण लागत	₹706.51 करोड़

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल द्वारा आर्थिक सुधारों और समावेशी संवृद्धि पर नीतिगत सलाह देने हेतु किस विशेष निकाय के गठन को मंजूरी दी गई है?

A बिहार आर्थिक सलाहकार परिषद (BEAC)

B बिहार राज्य नीति आयोग

C बिहार सतत विकास प्राधिकरण

D राज्य राजस्व एवं वित्त संवर्धन बोर्ड

उत्तर / Answer: A — केंद्र की PMEAC की तर्ज पर मुख्यमंत्री को आर्थिक विषयों पर सलाह देने हेतु 5 सदस्यीय बिहार आर्थिक सलाहकार परिषद (BEAC) के गठन को मंजूरी दी गई है।

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

अमृत 2.0 योजना के तहत बिहार कैबिनेट ने पटना जलापूर्ति परियोजना हेतु कितनी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है?

A ₹1,245.50 करोड़

B ₹1,794.32 करोड़

C ₹2,108.75 करोड़

D ₹980.20 करोड़

उत्तर / Answer: B — पटना और दानापुर क्षेत्र के 75 वार्डों में 2.18 लाख से अधिक घरों को नल से जल उपलब्ध कराने हेतु ₹1,794.32 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है।

पूरा लेख, PDF और रोज़ के अपडेट

Full article, PDF & daily updates

हिंदी और English दोनों में पढ़ें

aajkagk.com

पेज को **Follow** करें और **Share** करें

Follow the page & share with friends